कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–3 / 45 / 2014 / 10–11 / 5 / 2758 भोपाल, दिनांक 28/08/2020

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

प्रति,

श्री बिजेन्द्र स्वरूप,
सहायक वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः–पन्ना जिले के अंतर्गत मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 426.763 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-37/2017-FC दिनांक 03.05.2018

––0––

महोदय,

विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी की गयी सैद्वांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर निम्नानुसार प्रेषित हैः–

S.No	Particular / Condition	Compliances
i	Legal status of the diverted forest land shat remain unchanged;	आवेदक संस्था इस शर्त से सहमत है। इस शर्त के संबंध में आवेदक संस्था का वचन पत्र Annexure-I पर संलग्न है।
ii	The proposed dam is 8 km long & C-shaped earthen dam at panna District. In 2016 mansoon there were two (2) dam burst cases at panna. Looking in to length of dam, shape of dam, earthen dam, pre 2015 design and act of violation is also reported. So a study from reputed national institute for required structural approval shall be undertaken and the recommendations be implemented by the user agency to avoid any possible unforced conditions;	इस शर्त के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके विभाग में डिजाईन करने के लिये पृथक से एक विंग निर्मित है जिसके द्वारा इस बांध की डिजाईन की गई है। आवेदक संस्था द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि विभाग की इस विंग द्वारा पूर्व में बाणसागर, मड़ीखेड़ा, मोहनपुरा, कुण्डलिया आदि बांधों की डिजाईन का कार्य किया है। यह बांध प्रस्तावित बांध से बड़े है। आवेदक संस्था द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि बांध निर्माण के समय पूर्ण सावधानी बरती जायेगी।

iii	As the CA site is rugged with inert shallow soil strata, therefore the C.A. scheme would be revised so as to augment moisture regime in the area and planting indigenous species only.	वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण पन्ना द्वारा गैर वन भूमि के अनुसार 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वनीकरण की योजना तैयार की गई है। क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य हेतु प्रावधान रखा गया है।
iv	Compensatory afforestation shall be raised over equivalent non forest and least 1000 plants will be planted (426.763 ha x 1000 plants/ha= 426763 plants) on the non-forest land. CA cost will be revised accordingly and CA cost will be deposited the CA area for reducing biotic interference will be erected by the forest department at the cost of the user agency.	वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण पन्ना द्वारा गैर वन भूमि के अनुसार 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वनीकरण की योजना तैयार की गई है। क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य हेतु प्रावधान रखा गया है। यह योजना रू. 12.2122 करोड़ की तैयार की गई है। इस रोपण योजना की तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर द्वारा जारी की गई है। रोपण योजना तथा तकनीकी स्वीकृति Annexure-II पर संलग्न है। आवेदक संस्था द्वारा यह राशि ऑनलाईन जमा कर दी गई है।
v	25% of the CA cost will be deposited in addition to normal CA cost in CA managed by Ad-Hoc CAMPA for the soil & moisture conservation activities on the CA land.	वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण पन्ना द्वारा गैर वन भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण की तैयार की गई योजना में मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों हेतु प्रावधान रखा गया है। रोपण योजना तथा मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों हेतु यह योजना रू. 12.2122 करोड़ की तैयार की गई है।
vi	The catchment area treatment (CAT) Plan will be prepared by the state government and the cost of the CAT will be deposited in the CAF managed by AD-hoc CAPMA .	इस बांध के जल ग्रहण क्षेत्र की योजना तैयार की गई है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर द्वारा जारी की गई है। मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति की छायाप्रति Annexure-III पर संलग्न है। आवेदक संस्था द्वारा इस योजना की वन क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यो हेतु आवश्यक राशि रू. 83.49 लाख की राशि पोर्टल के माध्यम से भुगतान कर दी गई है।
vii	As the area of Panna Tiger Reserve is involved 5 % of the NPV shall be deposited and used for Wildlife Management plan in Panna Tiger Reserve.	प्रस्ताव में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बफर क्षेत्र का 42.831 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। आवेदक संस्था द्वारा इस वन क्षेत्र की 5 प्रतिशत एन.पी.वी. की राशि रू. 13.406 लाख का भुगतान पोर्टल के माध्यम से कर दिया है।

viii	Since 11 families settled over 22.683 ha in North Panna forest division & 40 families settle over 39.52 PTR area involved, the R&R pian shall be prepared and submitted by the User Agency.	आवेदक संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि इस परियोजना में प्रभावित परिवारों को "Right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013" combined with National Rehabilitation Policy 2013 के अनुसार निराकृत किया जायेगा। इस संबंध में आवेदक संस्था का वचन पत्र Annexure-IV पर संलग्न है।
ix	Penal CA shall be raised over 426 Ha of the degraded forest land forest land since work has been done in violation of FC.	इस शर्त के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा खसरा क्रमांक 928, 931 एवं 932 में कार्य प्रारम्भ किया गया था। यह खसरे निजी किसानों के नाम से दर्ज थे। इस भूमि के अभिलेखों के अनुसार यह राजस्व भूमि में थे तथा राजस्व विभाग द्वारा इनके पट्टे भी संबंधित किसानों को दिये गये थे। कार्य प्रारम्भ होने के बाद वन विभाग द्वारा कार्य रोकते हुये वन अपराध प्रकरण क्रमांक 1513/08 दिनांक 09.07.2015 दर्ज किया गया था। इस वन अपराध प्रकरण का निराकरण वनमण्डलाधिकारी द्वारा कर दिया गया है तथा इस वन अपराध प्रकरण में दण्ड की राशि जमा कराई जा चुकी है। इस प्रकार प्रकरण में राजस्व-वन सीमा विवाद के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। अतः आवेदक संस्था पर यह दण्ड रोपित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। वन अपराध प्रकरण भी उचित दण्ड अधिरोपित करते हुये समाप्त किया जा चुका है।
x	Penal NPV will be imposed as per the guideline of the ministry as applicable in this case.	शर्त क्रमांक ix में दिये विवरण अनुसार जिस भूमि पर कार्य प्रारम्भ किया गया था वह अभिलेखों के अनुसार यह राजस्व भूमि थे। अतः आवेदक विभाग द्वारा जानबूझकर यह कृत्य नहीं किया गया है। अतः आवेदक संस्था पर यह दण्ड रोपित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। वन अपराध प्रकरण भी उचित दण्ड अधिरोपित करते हुये समाप्त किया जा चुका है।

xi	The area under diversion should be measured agiain using Total station method as area proposed found to be more (661.54 ha) through DSS as compared to proposed.	इस शर्त के संबंध में आवेदक संस्था तथा वन विभाग द्वारा प्रभावित वन भूमि का क्षेत्र 426.763 हेक्टेयर ही पाया गया है।
xii	The proposal attracts Para 2 (ii) of guideline F.No 8-37/2017- FC dt. 03.05.2018 and based on which FC clearance for protected area may be considered after obtaining the Wildife Clearance. Wildife Clearance for this project is not submitted and the same may be obtained by the state government.	इस प्रस्ताव पर राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 48वीं बैठक दिनांक 27.03.2018 में विचार किया गया था तथा इस प्रस्ताव के संबंध में वन्यप्राणी अनुमोदन प्राप्त हुआ था। बोर्ड की इस बैठक का विवरण Annexure-V पर संलग्न है।
xiii	The proposed dam is 8 km long & C- shaped earthen dam at Panna Distt. In 2016 monsoon there were two (2) dam 2015 burst cases at Panna. Looking in to Length of dam, shape of dam, earthen dam, pre 2015 design and act of violation is also reported. So it is proposed to seek a study from reputed national institute for required structural approval for taking triple the precaution to avoid any possible unforced conditions.	शर्त क्रमांक (ii) में दिये विवरण अनुसार।
xiv	The quantum of penalty of violations committed by user agency shall be arrived in accordance with guidelines issued by this Ministry vide no . 11-42/2017-FC dated 29th January 2018	शर्त क्रमांक (ix) एवं (x) में दिये विवरण अनुसार।
xv	Complete compliance of the FRA 2006 shall be done by the state Govt. before diverting the forest land for non- forestry purpose in the proposed project.	आवेदक संस्था द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो Annexure-VI पर संलग्न है।

xvi	It has (Seen reported that the District Collector, Panna Madhya Pradesh has issued certificate dated 21.09.2015 for diversion of 426.763 ha of forest land in favour of certificate dated 21.09.2015 for diversion of 426.763 ha of forest in fovour of Water Resources Department Panna Distt. For Construction of Majhgaon Medium Irrigation project Panna district in the State of Madhya Pradesh without approval under FC Act. The matter should be investigated under section 3A/3B of the FC Act by the Regional office and reported along with the action taken report against erring officials (those involved in non-forestry use of forest land) already initiated by the State Government.	शर्त क्रमांक (ix) एवं (x) में दिये विवरण अनुसार।
xvii	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India toposheet of 1,50,000 scale.	आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो Annexure-VII पर संलग्न है।
xviii	The Non- Forest land to be transferred and mutated in favour of the state Forest Department for raising Compensatory Afforestation shall be notified as reserved forest under Section- 4 or Protected forest under under Section – 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section (s) of the local Forest Act. The Nodal officer must report compliance within a period of 6 month from the date of grant of final approval and send 29 of the Indian Forest Act, 1927 or Under the relevant section of the local Forest Act as the case may be, to this Ministry for information and record.	आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई गैरवन भूमि का नामांतरण वन विभाग के नाम किया जा चुका है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत फार्म–पी–2 Annexure-VIII पर संलग्न है। इस गैर वन भूमि को वन घोषित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

xix	The User Agency shall transfer the cost of rainsing and maintaining the compensatory afforestation at the current wage rate in consultation with state Forest Department in the account of Ad-hoc CAMPA of the concerned State through cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त क्रमांक (iv) में दिये विवरण अनुसार।
xx	The Uses Agency shall provide additionally 25% of the CA cost toward soil and Moisture Conservation measures in the proposed CA area as per site requirement and the said amount may be deposited in the account of Ad-hoc CAMPA of the concerned State through online e-portal only	शर्त क्रमांक (v) में दिये विवरण अनुसार
xxi	The User Agency shall transfer online, the Net present Value (NPV) Of the forest land of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-312007- FC dated 05.02.2009. The Requisite funds shall be transferred though online portal into Ad-hoc CAMPA account of the state Concerned.	आवेदक संस्था द्वारा एन.पी.वी. की राशि रू. 2671.54 लाख की राशि पोर्टल के माध्यम से जमा की गई है।
xxii	Any fund received from the user agency under the project and deposited in the State forest Department account except the funds realized for regeneration/ demarcation of safety zone, shall. oe transferred though online portal into Ad-hoc CAMPA account of the State Concerned.	आवेदक संस्था द्वारा सभी राशियां पोर्टल के माध्यम से जमा की गई है।
xxiii	The user agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank online only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.	आवेदक संस्था द्वारा सभी राशियां पोर्टल के माध्यम से जमा की गई है।

-7-

xxiv	At the time of payment on the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV if so determined as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.	आवेदक संस्था द्वारा इस संबंध में वचन पत्र प्रस्तुत किया है, जो Annexure-IX पर संलग्न है।
xxv	The approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan shall be implemented at the cost of user agency. The commensurate cost of CAT plan will be deposited in Compensatory Afforestation Fund of the Sate.	शर्त क्रमांक (vi) में दिये विवरण अनुसार।
xxvi	The State Govt. shall submit a certificate, that site for CA is suitable and free from all encroachments and other encumbrances, under the signature not below the rank of Nodal Officer (FCA) in the State Government.	वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण पन्ना का इस संबंध में प्रमाण पत्र Annexure-X पर संलग्न है।
xxvii	User agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act 1986 if required.	आवेदक संस्था द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में यह अवगत कराया है कि भारत सरकार में EAC held on 28.01.2019 में एजेण्डा क्रमांक 21.8 में इसे स्वीकृति दी गई है, जो Annexure-XI पर संलग्न है।
xxviii	The State Government shall ensure that the forest land located between FRI, and the FRL-4 meters may be afforested by planting appropriate indigenous tree species.	आवेदक संस्था द्वारा यह शर्त मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदक संस्था का वचन पत्र Annexure-XII पर संलग्न है।
xxix	The User Agency shall undertake afforestation along the periphery of the reservoir.	आवेदक संस्था द्वारा यह शर्त मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदक संस्था का वचन पत्र Annexure-XIII पर संलग्न है।
xxx	User Agency shall Provide free water for the Forestry related projects.	आवेदक संस्था द्वारा यह शर्त मान्य की गई है।
xxxi	Layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.	आवेदक संस्था द्वारा यह शर्त मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदक संस्था का वचन पत्र Annexure-XIV पर संलग्न है।

xxxii	No labour camp/huts shall be established on the forest land.	आवेदक संस्था द्वारा यह शर्त मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदक संस्था का वचन पत्र Annexure-XV पर संलग्न है।
xxxiii	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal and under no circumstances be transferred to any other agency department or person.	आवेदक संस्था द्वारा यह शर्त मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदक संस्था का वचन पत्र Annexure-XVI पर संलग्न है।
xxxiv	Felling of tress on the forest land being diverted shall be reduced to the bare minimum and the trees should he felled under strict supervision of the State Forest Department.	यह कार्य वन विभाग द्वारा किया जायेगा।
xxxv	The State Government ensure that the user agency shall implement the R&R plan as per the R&R policy of state Government in consonance with Notional R&R Policy Government of India before the commencement of the project work. The said R&R plan will be monitored by the State Government/ Regional Office of MoEE&CC along with indicators for monitored for monitoring and expected observable milestones.	आवेदक संस्था द्वारा यह शर्त मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदक संस्था का वचन पत्र Annexure-IV पर संलग्न है।
xxxvi	User agency in consultation with the State Forest Department shall create and maintain alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting tress are to be cleared in this project. Bird nests artificially made out of eco-friendly materials shall be used in the area including forest area and human settlements adjoining the forest area being diverted for the project.	आवेदक संस्था द्वारा यह शर्त मान्य की गई है। आवेदक संस्था के व्यय पर यह कार्य वन विभाग द्वारा किया जावेगा।
xxxvii	State Government shall complete settlement of right, in terms of this scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 if any on the land to be diverted and submit the documentary evidence as prescribed by this forest land to be diverted and submit the documentary evidence as prescribed by this Ministry in its letter No. I I- 9/1998-FC (pt.) dated 03.08.2009 read with 05.07.2013 in support there of.	आवेदक संस्था द्वारा यह शर्त मान्य की गई है। आवेदक संस्था द्वारा इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

xxxviii	The user agency shall provide alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the near by forest areas.	आवेदक संस्था द्वारा यह शर्त मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदक संस्था का वचन पत्र Annexure-XVII पर संलग्न है।
xxxix	Boundary of the forest land proposed to be diverted shall be demarcated on ground at the project cost by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars each inscribed with its serial number forward and back bearing distance from pillar to pillar and GPS co-ordinates.	प्रभावित वन भूमि आवेदक संस्था को हस्तांतरण करने के पूर्व यह कार्यवाही वन विभाग द्वारा सम्पादित कर ली जायेगी।
xl	The State Government shall maintain the character of the projects as an irrigation project and to ensure continued benefit to the farmers in the command area no more diversion of water from the project for industrial projects will be permitted in future.	सहमत।
xli	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forests& wildlife.	सहमत।
xlii	The user agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above conditions to the State Government concerned Regional Office and this Ministry by the end of March of every yearregularly and	सहमत।
xliii	The user agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules Regulations Guidelines relevant hon's ble Court Order (s) and National Green Tribunal (NGT) Order (S) if any pertaining to this for the time being in force as applicable to the project.	सहमत।

अतः प्रस्ताव में औपचारिक अनुमोदन जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक / एफ–3 / 45 / 2014 / 10–11 / 5 / 2759 भोपाल, दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, 1250, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर वृत्त छतरपुर (म0प्र0)।
3. वन मंडल अधिकारी, सामान्य वन मंडल, उत्तर पन्ना, मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्र संचालक, पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना (म0प्र0)
5. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पन्ना (म0प्र0)।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

28/8/2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

PROFORMA FOR VERICICATION OF DEPOSITS IN COMPENSATORY AFFORESTATION FUND

1	Name of Regional Office	Bhopal
2	State/Distt/Forest Division to which the proposal relates	State : M.P. District : Panna Division : North Panna
3	Name of User Agency, nature of proposal	WRD
4	nature and category of proposal	Irrigation
5	Proposal number	FP/MP/IRRIG/7121/2014
6	Extent of forest area involved	426.763 ha.
7	Whether original or extension	Original
8	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional forest area and if so, specify	NA
9	Date of Ist stage clearance	03-05-2018
10	Extent of CAMPA charges, head wise viz,: (a) Compensatory Afforestation: (b) Additional CA (c) Penal CA (d) Catchment Area Treatment (e) NPV for Wildlife Area (f) Additional Charges for diversion of area falling under notified/protected areas (g) Net Present Value (h) Any Other Charges /levies (Penal Net Present Value)	a) 12,21,22,000 /- b) N/A c) N/A d) 83,49,425/- e) 13,40,610/- f) N/A g) 26,71,53,638 /- h) N/A
	Total	**39,89,65,673/-**

11	Whether payment made through challan of othervise in case of online payment details of challan				Through Challan		
12	Details of deposits						
S No.	Type of deposit (NPV/CA/IWMP/Others (specify))	Whether by RTGS/DD/ NEFT (specify)	UTR / DD No.	Amount deposited (Rs.)	Date of deposit	Name of Bank from which amout transferred to account of CAF	Bank Account of CAF managed by CAMPA in which fund deposited
1	CA	RTGS/ NEFT	-	12,21,22,000	20/08/2019	Corporation Bank , New Delhi - 110003	Corporation Bank
2	Catchment Area Treatment Plan			83,49,425	28/09/2018		
3	NPV for Wildlife Area			13,40,610	28/09/2018		
4	NPV			26,71,53,638	28/09/2018		
Total				**39,89,65,673/-**			

Sd/- 29/8/2022

(Sunil Agarwal)
APCCF (Land Management)
& Nodal officer FCA
Madhya Pradesh, Bhopal